CC MM YY KK

RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. बुधवार, 6 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 161 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु.

संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के लिए विचार भेजने की अपील की

नई दिल्ली – स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले भाषण के संबंध में अपने विचार और सुझाव साझा करने की अपील की है। एक्स पोस्ट पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं अपने साथी भारतीयों के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं!" उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे MyGov और NaMo ऐप पर खुले मंच पर अपने विचार व्यक्त करें कि वे इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या अवधारणाओं को प्रतिबिंबित होते देखना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.mygov.in/group-issue/let-your-ideas-and-suggestions-be-part-pm-modis-independence-day-speech-2025/ पर जाएं।

पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के बीच अंतर-सांस्कृतिक पर्यटन

नई दिल्ली 5 नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान)' शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, पर्यटन संपर्क को मज़बूत करने के उद्देश्य से, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और दक्षिण भारत सहित देश भर में 53 पर्यटन आरसीएस मार्ग पर्यटन - आरसीएस (टीआरसीएस) के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इन मार्गों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रतिपूर्ति से वित्त पोषित किया गया है, जिससे देश के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों तक सीधी हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई है। यद्यपि आरसीएस उड़ान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों और दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों के बीच कोई सीधी हवाई संपर्क सुविधा नहीं है, फिर भी कनेक्टिंग उड़ानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क सुविधा उपलब्ध है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कुल 90 मार्ग चालू किए गए हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में 10 हवाई अड्डों और 2 हेलीपोर्ट को जोड़ते हैं। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में थीम-आधारित सर्किट पर भारत गौरव ट्रेनों की कुल 17 यात्राएँ संचालित की गईं, जिनमें 9,246 पर्यटकों ने तमिलनाडु का भ्रमण किया। इन 17 यात्राओं में से, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) की 4 यात्राएँ शामिल थीं और 1,923 पर्यटकों ने तिरुचिरापल्ली (त्रिची) का भ्रमण किया।

डॉ. मुधोजी भोसले द्वारा ग्लोबल वेलनेस सेंटर का उद्घाटन

नागपुर – माँ गायत्री बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित "ग्लोबल वेलनेस सेंटर" का उद्घाटन माननीय डॉ. मुधोजी भोसले (नागपुर के महाराजा) द्वारा बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को नीलकमल हाउसिंग सोसाइटी, नरसाला, नागपुर में किया गया। इस केंद्र में पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी विभिन्न प्रकार की उपचार पद्धतियाँ प्रदान की जाएँगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. सुरेश पाशी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ नागपुर जिला अध्यक्ष डॉ. प्रीति मनमोड़े, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सतीश कराले, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष डॉ. विनोद ढोबले, ग्लोबल वेलनेस सेंटर निदेशक डॉ. सुधीर मोगरे, डॉ. स्मिता मोगरे ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह जानकारी डॉ. सुधीर मोगरे, निदेशक "ग्लोबल वेलनेस सेंटर" एमडी संख्या 9850341453 ने एक प्रेस नोट द्वारा दी है।

महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा

मराठी सिनेमा महाराष्ट्र की शान

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी फिल्म उद्योग, रंगमंच और कलाकार महाराष्ट्र की शान हैं और दादासाहेब फाल्के की फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' के रूप में बोया गया यह बीज आज वटवृक्ष बन गया है। वह वर्ली के डोम स्थित एसवीपी स्टेडियम में महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय द्वारा आयोजित लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 और छत्रपति शिवाजी महाराज महावरस पुरस्कार 2025 के वितरण समारोह में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी रंगमंच दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रंगमंच है। मराठी कलाकारों ने छोटे पर्दे, बड़े पर्दे, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों में अतुलनीय योगदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह न केवल कलाकारों, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों का भी ईमानदारी से सम्मान करे। फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आपके पीछे पूरी दृढ़ता से खड़ी है। अनुपम खेर के बहुमुखी

अभिनय की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अपनी पहली ही फिल्म में 70 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने वाले खेर आज भी उसी उत्साह के साथ अभिनय कर रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने मुक्ता बर्वे के 360-डिग्री अभिनय कौशल, खासकर 'चार चौघी' में उनके एकालाप, और महेश मांजरेकर के सशक्त अभिनय और निर्देशन की प्रशंसा की। ग़ज़ल गायक भीमराव पंचाले का ज़िक्र करते हुए, श्री फडणवीस ने कहा, "सुरेश भट्ट और भीमराव पंचाले की जोड़ी ने मराठी ग़ज़लों को अविस्मरणीय ऊंचाइयों तक पहुँचाया।" उन्होंने कहा, "शिवाजी महाराज के नाम पर विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करना महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "मराठी फिल्म उद्योग हमारा गौरव है और मेरा मानना है कि भविष्य में यह और भी अधिक समृद्ध होगा।"

मुंबई में किसी भी स्थान पर फिल्मांकन की अनुमति अब निःशुल्क दी जाएगी।

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने बताया कि राज्य के विभिन्न फिल्म निर्माण स्थलों पर किफायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मराठी फिल्मों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए रवींद्र नाट्य मंदिर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मराठी फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 'एफएम' रेडियो पर मराठी गीतों और कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करने के संबंध में एफएम रेडियो चैनलों के साथ चर्चा की गई है और इसके लिए एक पुरस्कार योजना की भी घोषणा की गई है। शेलार ने यह भी कहा कि अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने नेटफ्लिक्स के लॉस एंजिल्स मुख्यालय में मराठी फिल्मों के लिए जगह की माँग की।

.....अंदर के पेज पर

खाद्य विषाक्तता की घटनाओं को रोकने मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी

मुंबई – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार के स्थानीय निकायों के निजी अनुदानित एवं आंशिक अनुदानित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन का लाभ प्रदान किया जाता है। इस मध्याह्न भोजन के कारण होने वाली खाद्य विषाक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए, स्कूल शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की हैं। इस योजना में, छात्रों को पौष्टिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अनाज के भंडारण, पकाने, भोजन वितरण और स्वच्छता के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अनाज और अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच, रसोई की सफाई, भोजन का स्वाद लेना, रिकॉर्ड रखना, पानी की शुद्धता सुनिश्चित करना और भोजन के नमूनों को 24 घंटे सुरक्षित रखना जैसे उपाय अनिवार्य किए गए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य, शिक्षकों, रसोइयों, सहायकों, शिक्षा अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें खाद्य विषाक्तता की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता, नमूने की जाँच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। इस प्रक्रिया को तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं तथा कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का उर्वरक के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहीत

भारत सरकार ने पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में वैकल्पिक उर्वरकों अर्थात् जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, डी-ऑइल केक, जैविक कार्बनिक वर्धक और नैनो उर्वरक को अधिसूचित किया है पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारंपरिक खेती को 'परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)' के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है पीएम-प्रणाम योजना में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किसी वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी लाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है, जो उर्वरक सब्सिडी में बचत के 50% के बराबर है

भारत सरकार उर्वरक के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के सिद्धांत को प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2014 में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य राज्यों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता करना है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग, साथ ही साथ जैविक खाद एवं जैव-उर्वरकों के साथ सहायक पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपयोग शामिल है, जिससे मिट्टी की सेहत और उसकी उत्पादकता में सुधार किया जा सके। मिट्टी के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संसाधित किया जाता है और विभिन्न मानकों के लिए विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि पीएच, विद्युत चालकता (ईसी), कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पौटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन) आदि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषकता की स्थिति की जानकारी देता है और मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश करता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 25.13 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों पर 93781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख नमूना प्रदर्शन और 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

भारत सरकार ने पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में वैकल्पिक उर्वरकों अर्थात् जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, डी-ऑइल केक, जैविक कार्बन वर्धक और नैनो उर्वरक को अधिसूचित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारंपरिक खेती को 'परंपरागत कृषि विकास योजना' के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पीकेवीवाई के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों के लिए सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

पैंगोंग त्सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी की

तीन प्रमुख राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थानों के संयुक्त अभियान दल ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। देश के प्रमुख राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थानों जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस) पहलगाम; नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) उत्तरकाशी, और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई) दार्जिलिंग के प्रशिक्षकों वाले एक संयुक्त अभियान दल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों माउंट मेराग-III (6,480 मीटर) तथा माउंट कांगजू कांगड़ी (6710 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। इस अभियान को जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल हेम चंद्र सिंह द्वारा जुलाई, 2025 को सोनमर्ग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उन्होंने ही तीनों राष्ट्रीय संस्थानों के एक अनुभवी दल का नेतृत्व किया। इस दल में शामिल पर्वतरोही हैं: सब मेजर/ऑनरी लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) रफीक अहमद मलिक (जेआईएमएंडडब्ल्यूएस), हवलदार सज्जाद हुसैन (जेआईएमएंडडब्ल्यूएस), एनके भरत सिंह (जेआईएमएंडडब्ल्यूएस), हवलदार/एनए योगेश (जेआईएमएंडडब्ल्यूएस), सब मेजर हजारी लाल (एनआईएम), नायब सूबेदार भूपिंदर सिंह (एनआईएम), श्री रॉबिन गुरुंग (एचएमआई), श्री जुबिन राय (एचएमआई)।

140 करोड़ का रिकॉर्ड अर्जित, शाह ने दी बधाई

नई दिल्ली – रेप्को बैंक ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को वर्ष 2024-25 के लिए 22.90 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने रेप्को बैंक की टीम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 140 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने के लिए हार्दिक बधाई दी। गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस बैंक ने दक्षता, समर्पण और व्यावसायिकता का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो सहकारी क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। रेप्को बैंक ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को वर्ष 2024-25 के लिए 22.90 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने रेप्को बैंक की टीम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 140 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने के लिए हार्दिक बधाई दी।

अमित शाह ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस बैंक ने दक्षता, समर्पण और व्यावसायिकता का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो सहकारी क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। टीम को उसके भविष्य के सफर के लिए शुभकामनाएँ। रेप्को बैंक के अध्यक्ष श्री ई. संथानम, निदेशक–रेप्को बैंक और रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष श्री सी. थंगराजू और प्रबंध निदेशक श्री ओ.एम. गोकुल ने गृह मंत्री को चेक सौंपा। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सचिव, सीमा प्रबंधन डॉ. राजेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। रेप्को बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 140 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया और 30% लाभांश दिया, जो सहकारी समिति के इतिहास में सबसे अधिक है। रेप्को बैंक, भारत सरकार का एक उद्यम है। भारत सरकार के पास रेप्को बैंक में 50.08% हिस्सेदारी है और यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

गढ़वाल राइफल्स को वीरता पदक प्रदान किए

गढ़वाल राइफल्स की द्वितीय बटालियन के वीर अधिकारी कैप्टन चंद्र नारायण सिंह, महावीर चक्र (मरणोपरांत) की 60वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, कैप्टन ने 1965 के भारत- पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस वीर योद्धा के परिवार ने उनकी चिरस्थायी विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट को उनके शौर्य और अन्य सेवा पदक प्रदान किए। एक भावुक क्षण में, दिवंगत अधिकारी के भाई श्री सुखदेव सिंह ने रेजिमेंट को महावीर चक्र (एमवीसी) और अन्य सेवा पदक प्रदान किए।

जीईएनसी के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेंद्र सिंह से की औपचारिक भेंट

नई दिल्ली – पदोन्नति से संबंधित और इसके लंबित मामलों को निपटाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल की सराहना की गई; संवाद के दौरान सीजीएचएस, 8वें वेतन आयोग, यूपीएस आदि पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने समय-समय पर बैठक के लिए वक्त देने और इस प्रकार उन्हें अपना दृष्टिकोण सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की। इस दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े हुए सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की सराहना की, जो कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति लगातार संवेदनशील

रही है और उनके सुझावों पर सहयोग करती रही है। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के लंबित मामलों को निपटाने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की पहल की प्रशंसा की, जिससे कर्मचारियों में अधिक स्पष्टता और मनोबल आया है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि इन कदमों से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और कैरियर प्रगति के ढांचे में अधिक स्पष्टता आई है। प्रतिनिधिमंडल ने समय-समय पर बैठक के लिए वक्त देने और इस प्रकार से उन्हें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया और इन मुद्दों पर सरकार की निरंतर भागीदारी में विश्वास व्यक्त किया।

जीईएनसी के प्रतिनिधियों ने अनेक सेवा संबंधी मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर जानकारी दी। इस बातचीत में कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने, परामर्श के लिए संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाने और सुधारों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत काफी रचनात्मक रही, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने व्यापक प्रणालीगत सुधारों और कर्मचारियों की चिंताओं पर जानकारी साझा की। कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक दक्षता के संदर्भ में 8वें वेतन आयोग, सीजीएचएस लाभों के युक्तिकरण और यूपीएस मानदंडों पर स्पष्टता से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया। डॉ. जितेंद्र सिंह, जिनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से प्राप्त जानकारी का स्वागत किया। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

CC MM YY KK

संपादक की कलम से

ब्लू कार्बन परियोजना

मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और नमक वाले दलदल जैसे नीले कार्बन इकोसिस्टम समुद्र तटीय इलाके में मौजूद हैं जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे संग्रहीत करते हैं। जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बताया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - एनएमसीजी) एक व्यापक नदी कायाकल्प पहल है। हालांकि यह मुख्य रूप से सीवेज उपचार, रिवरफ्रंट विकास, वनीकरण, आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण और जन जागरूकता पर केंद्रित है, जिनमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नीले कार्बन इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), देहरादून द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर गंगा के किनारे वैज्ञानिक तौर पर वनीकरण किया गया है। एनएमसीजी ने 2016-17 से नदी के किनारे वृक्षारोपण के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के वन विभागों को वित्त पोषित किया है।

मिलिंद दहिवले
संपादक

दिव्या देशमुख की शानदार सफलता बनेगी प्रेरणा

राज्य सरकार ने 3 करोड़ की राशि प्रदान, खिलाड़ियों को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास - मुख्यमंत्री

नागपुर - महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा खेल क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। खिलाड़ी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण, स्वस्थ आहार और विदेशी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन आवश्यक है। विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए ये सभी आवश्यक हैं। खिलाड़ियों को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व प्रतियोगिता में दिव्या देशमुख द्वारा प्राप्त शानदार सफलता देश के हजारों बालक-बालिकाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।

विश्व शतरंज चैंपियनशिप की विश्व विजेता ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख का नागरिक अभिनंदन स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग तथा महाराष्ट्र शतरंज संघ के सहयोग से कविवर्य सुरेश भट हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दिव्या को सम्मानित किया और उन्हें 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। महाराष्ट्र शतरंज संघ द्वारा भी 11 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें मध्य प्रदेश खेल महोत्सव समिति द्वारा भी सम्मानित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे, वित्त एवं योजना राज्य मंत्री एडवोकेट इस अवसर पर आशीष जायसवाल, विधायक सर्वश्री संदीप जोशी, अभिजीत वंजारी, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, महाराष्ट्र शतरंज संघ के अध्यक्ष एवं विधायक परिणय फुके, खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल दिग्गीकर, खेल एवं युवा सेवा आयुक्त शीतल तेली-उगले, पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, दिव्या के पिता डॉ. जितेंद्र देशमुख, माता डॉ. नम्रता देशमुख, महाराष्ट्र शतरंज संघ से संबद्ध जिला संगठनों के पदाधिकारी, शतरंज खिलाड़ी, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में नागपुर निवासी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिव्या ने छोटी सी उम्र में ही बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। शतरंज के लिए उत्साह, एकाग्रता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। शतरंज सौ से अधिक देशों में खेला जाने वाला खेल है। इसलिए दिव्या की सफलता बड़ी है। शतरंज में चीन का दबदबा था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के इस दबदबे को कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने तोड़ा। इसमें दिव्या ने मात्र 19 वर्ष की आयु में फाइनल राउंड में जीत हासिल की। उन्होंने कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और यह सम्मान समारोह देश के हजारों बालक-बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विश्वास व्यक्त किया कि दिव्या की सफलता हजारों बालक-बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी होगी।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने कहा कि जब कोई सफल खिलाड़ी बनता है तो उसके लिए परिवार, कोच और व्यवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस सफलता में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर लड़कियों को अवसर, उचित प्रशिक्षण और प्रेरणा मिले, तो वे दुनिया जीत सकती हैं। दिव्या ने इस बदलाव को साबित किया है। खेल मंत्री श्री कोकाटे ने कहा कि यह सफलता सभी के लिए अनुकरणीय है। राज्य सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को अवसर और धन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की विश्व चैंपियन ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने अपने विचार व्यक्त किए। शतरंज प्रतियोगिता में विश्व विजेता बनने के लिए राज्य सरकार ने बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। नागपुर मेरे लिए एक विशेष शहर है। इस सम्मान समारोह के लिए मैं नागपुरवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस सफलता के बाद, वे अगली विश्व प्रतियोगिताओं के लिए और भी अधिक तत्परता से तैयारी करेंगी।

महाराष्ट्र शतरंज संघ के अध्यक्ष ए. परिणय फुके ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत में आयोजित होने वाला शतरंज विश्व कप महाराष्ट्र में भी आयोजित किया जाना चाहिए। खेल एवं युवा सेवा आयुक्त शीतल तेली उगले ने कार्यक्रम की शुरुआत की। ग्रैंडमास्टर अभिजीत कुंटे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - एनएमसीजी एक व्यापक नदी कायाकल्प पहल

मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और नमक वाले दलदल जैसे नीले कार्बन इकोसिस्टम समुद्र तटीय इलाके में मौजूद हैं जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे संग्रहीत करते हैं। जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बताया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - एनएमसीजी) एक व्यापक नदी कायाकल्प पहल है। हालांकि यह मुख्य रूप से सीवेज उपचार, रिवरफ्रंट विकास, वनीकरण, आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण और जन जागरूकता पर केंद्रित है, जिनमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नीले कार्बन इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), देहरादून द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर गंगा के किनारे वैज्ञानिक तौर पर वनीकरण किया गया है। एनएमसीजी ने 2016-17 से नदी के किनारे वृक्षारोपण के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के वन विभागों को वित्त पोषित किया है।

पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में अलग लक्ष्य के रूप में "ब्लू कार्बन इकोसिस्टम" का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि, वे 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने पर जोर देते हैं। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा गया है कि मैंग्रोव, समुद्री घास और नमक वाले दलदल जैसे ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का संरक्षण और पुनर्स्थापन भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही अनुकूलन का समर्थन करता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय मिशन के "मैंग्रोव और कोरल रीफ्स के संरक्षण और प्रबंधन" घटक के तहत, 2017-2018 से 2022-2023 की अवधि के दौरान पिचवरम सहित मैंग्रोव पुनर्स्थापन से जुड़ी गतिविधियों के लिए तमिलनाडु राज्य को कुल 220.43 लाख रूपये की राशि मंजूर की है। हाल ही में, मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय आवास स्थलों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) की घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) पर शुरू की गई मिष्टी का उद्देश्य मैंग्रोव इकोसिस्टम को उनकी उच्च कार्बन भंडारण क्षमता और तटीय जैव-रक्षण के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्नत बनाना है। इस पहल को राज्य कैम्पा, मनरेगा और अन्य राज्य योजनाओं के साथ संयोजन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कैम्पा से गैप-फंडिंग शामिल है। तमिलनाडु राज्य ने अभी तक मिष्टी के तहत धन प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत नहीं की है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 28 जून, 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया है। सीसीटीएस के दो तंत्र हैं: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। भारत सरकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति सहित विभिन्न पहलों और निकायों के माध्यम से राज्यों को कार्बन क्रेडिट तंत्र विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। हालांकि, सीसीटीएस के तहत तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य को कोई तकनीकी सहायता नहीं दी गई है। मंत्रालय के पास वर्तमान में ब्लू कार्बन परियोजनाओं के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या कोई समर्पित कार्यान्वयन ढांचा नहीं है। हालांकि, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास और नमक वाले दलदल को लक्षित करते हुए पुनर्स्थापन प्रयास किए गए हैं। इन पहलों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी रही है, और पुनर्स्थापन परिणामों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उनके पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का लाभ उठाया गया है।

अनन्या पांडे का बना नया दोस्त

बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने सेट पर अपने नए 'दोस्त' का खुलासा किया। अभिनेत्री ने मैथ्यू मैककोनाघी की किताब 'ग्रीनलाइट्स' की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, रटेक के बीच मेरी नई दोस्त।र अभिनेत्री फिलहाल अपनी दसवीं फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में अनन्या ने अपनी पहली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से जुड़े एक पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें वह अपने लोकेशन के बारे में बात करती नजर आईं। अभिनेत्री अपनी दसवीं प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए उसी शूटिंग लोकेशन पर लौटी थीं।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मौजूदा शूटिंग लोकेशन की झलक दिखाई। क्लिप में अभिनेत्री एक कार से हरे-भरे पेड़ों से घिरी एक खूबसूरत सड़क के बीच से दिखाई दीं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा, लगभग 7 साल पहले स्टूडेंट ऑफ दी ईयर 2 की शूटिंग की थी! इसी लोकेशन पर और अब मैं अपनी 10वीं फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर कर रही हूं।

अनन्या पांडे ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस फिल्म पर काम कर रही हैं। हालांकि, उनके पास कुछ रोमांचक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें अक्षय कुमार और आर माधवन के साथ 'केसरी चेप्टर 2' और साथ ही ' चांद मेरा दिल' भी शामिल है। पिछले साल नवंबर में फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुलासा किया था कि अनन्या रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' में 'किल' अभिनेता लक्ष्य लालवानी के साथ नजर आएंगी। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी रोमांटिक-कॉमेडी साल 2025 में रिलीज होने वाली है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी कृतिका कामरा

जानीमानी अभिनेत्री कृतिका कामरा मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में ऐतिहासिक कला रूपों के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी। कृतिका कामरा जल्द ही अपने गृहनगर मध्य प्रदेश जाएंगी, जहां वे उन महिला कारीगरों से मुलाकात करेंगी, जो उनके 2024 में शुरू किए गए अनोखे फैशन पहल का अहम हिस्सा हैं। यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और पारंपरिक कला को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कृतिका का मानना है कि हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए।

जो हमारी रचनात्मक दृष्टि को साकार करने में मदद करते हैं। कृतिका अपने इस सफर में उन हुनरमंद महिला कारीगरों के साथ समय बिताएंगी, जिन्होंने उनके इस पहल को निरंतर सहयोग दिया है। वे इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं को अवसर देना और उनके योगदान को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर हथकरघा और कपड़ा उद्योग में, जिसका चंदेरी, मध्य प्रदेश से गहरा जुड़ाव है।

कृतिका कामरा ने कहा,मध्य प्रदेश मेरे दिल के बहुत करीब है। यह सिर्फ मेरा गृहनगर नहीं है, बल्कि यही वह जगह है जहां से मुझे अपने एथनिक वियर के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं हमेशा से अपने राज्य के लोगों, खासकर महिला कारीगरों, की किसी न किसी तरह मदद करना चाहती थी। मेरी सफलता में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा को पहचानना और उनकी सराहना करना मेरा कर्तव्य है।

रश्मिका ने थामा के सेट से पोस्ट किया शेयर

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों 'थामा' की शूटिंगमें व्यस्त हैं। उन्होंने फिल्म के सेट से बताया कि निर्देशक आदित्य सरपोतदार जानते हैं कि सही शब्दों का इस्तेमाल करके वह अभिनेत्री को खुश कर सकते हैं। रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में निर्देशक आदित्य सरपोतदार एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए शूटिंग के दौरान स्क्रीन पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। रश्मिका ने इस तस्वीर के साथ लिखाः मेरे निर्देशक हर बार मुझे रात की शूटिंग करने पर मजबूर करते हैं आइस बकेट मेरी ज़िंदगी की कहानी। तस्वीर में एक प्लास्टिक की बाल्टी है, जिस पर आइस बकेट लिखा हुआ था और रश्मिका ने इसे मज़ाकिया अंदाज में मेरी ज़िंदगी की कहानी कहकर, बार-बार रात की शूटिंग को लेकर हल्की शिकायत की।

अवसाद से जूझ रहे अमाल मलिक

मशहूर संगीतकार अमाल मलिक ने कहा है कि वह अवसाद से पीड़ित हैं और परिवार के साथ उनके रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं इसलिये वह अपने पारिवारिक सम्बन्ध को ख़त्म कर रहे हैं। अमाल मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में अपने और भाई संगीतकार अरमान मलिक के बीच बढ़ती दूरियों के लिए अपने माता-पिता को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं अपने दर्द के बारे में चुप नहीं रह सकता। सालों से, मुझे यह महसूस कराया जाता रहा है कि मैं कमतर हूं, जबकि मैं दिन-रात मेहनत करता रहा हूं।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी

डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस से 25 यात्री घायल

न्यूयॉर्क – सॉल्ट लेक सिटी से एम्स्टर्डम जा रही डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को बुधवार रात गंभीर तूफानी झटकों (turbulence) का सामना करना पड़ा, जिससे कई यात्री घायल हो गए। इस कारण फ्लाइट को आपात स्थिति में मिनियापोलिस-सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। सॉल्ट लेक सिटी से एम्स्टर्डम जा रही डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को बुधवार रात गंभीर तूफानी झटकों (turbulence) का सामना करना पड़ा, जिससे कई यात्री घायल हो गए। इस कारण फ्लाइट को आपात स्थिति में मिनियापोलिस-सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। इसके बाद राहत और बचाव दलों ने मोर्चा संभाल लिया। एयरलाइन के अनुसार चिकित्सकीय टीमों ने तुरंत फ्लाइट के यात्रियों को रिसीव किया और 25 लोगों को इलाज और जांच के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उड़ान के दौरान गंभीर चोटें दुर्लभ होती हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम में हो रहे बदलाव की वजह से अब इस तरह की घटनाएं अधिक सामान्य होती जा रही हैं। गौरतलब है कि मई 2024 में सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में भी गंभीर टर्बुलेंस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह कई दशकों में पहली बार था ,जब किसी प्रमुख एयरलाइन में टर्बुलेंस के कारण किसी की जान गई।

अमेरिका में F-35 लड़ाकू विमान क्रैश

अमेरिका – F-35 लड़ाकू विमान क्रैश, कैलिफोर्निया में हादसा, अब तक क्या-क्या पता लगा? अमेरिकी नौसेना को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नौसेना का एक F-35 लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया है। अमेरिका से एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अमेरिकी नौसेना का F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में विमान के पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया है। F-35 लड़ाकू विमान के क्रैश होने की ये घटना बुधवार को सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने विमान क्रैश होने के बारे में एक प्रेस बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक, बुधवार को कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास एक अमेरिकी नौसेना का F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। बयान में कहा गया है कि हादसे के वक्त पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया और शाम लगभग 6:30 बजे हुई इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। नौसेना ने अपने बयान में जानकारी दी है कि जो F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ उसे स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन VF-125 को सौंपा गया था, जिसे "रफ़ रेडर्स" के नाम से जाना जाता है। VF-125 एक फ्लीट रिप्लेसमेंट स्क्वाड्रन है, जो पायलटों और एयरक्रू को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय ने किया नाबालिग का यौन शोषण, 14 साल की सजा

सिंगापुर – सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक पर 11 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। इस अपराध में उसे दोषी ठहराये जाने के बाद अदालत ने 14 साल की सजा दी है। एक भारतीय नागरिक ने शर्मनाक करतूतें की हैं। 58 साल की उम्र का एक भारतीय नाबालिग किशोरी से यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है। बच्ची की उम्र महज 11 साल थी। वह उसकी दुकान में शाम के वक्त कुछ खरीदने आई थी, तभी दरिंदे ने मौका पाकर उसका जबरन यौन शोषण किया। अब अदालत ने दोषी को 14 साल की सख्त सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के अनुसार दोषी व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची का दो बार यौन उत्पीड़न किया था। उसे अब इस जुर्म में बृहस्पतिवार को 14 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। सिंगापुर उच्च न्यायालय ने कहा कि रामलिंगम सेल्वासेकरन (58) की उम्र अधिक होने के कारण उसे कोड़े तो नहीं मारे जाएंगे, लेकिन उसे कोड़ों के बदले 14 वर्ष, तीन महीने और दो सप्ताह की सजा दी जाएगी। 'द स्ट्रेट्स टाइम्स' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सेल्वासेकरन को अदालत ने सात जुलाई को दोषी करार दिया था। मामले के अनुसार ये अपराध 28 अक्टूबर 2021 को शाम लगभग चार बजकर 50 मिनट से पांच बजकर पांच मिनट के बीच तब हुआ, जब सिंगापुर के पश्चिमी तट पर जुरोंग वेस्ट स्थित उसकी एक दुकान पर बच्ची कुछ लेने आई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सेल्वासेकरन ने खुद अपना पक्ष रखा। उसे सजा 30 जुलाई को सुनाई गई, लेकिन उसने खुद को बेगुनाह बताया।

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड ने औषधीय पौधों के संरक्षण में जन जागरूकता बढ़ाने अहम समझौता

नई दिल्ली – पहला समझौता, दुर्लभ और लुप्तेप्राय औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म संरक्षण के लिए एनएमपीबी और ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के बीच हुआ। दूसरा समझौता, एम्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधीय पौध उद्यान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स, नई दिल्ली के बीच हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने निर्माण भवन में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की, औषधीय पौधों के संरक्षण और जागरूकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों के संरक्षण से संबंधित आज दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में इन दोनों समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहले समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और पुणे, महाराष्ट्र के ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर ने हस्ताक्षर किए। दूसरे त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षर किए गए। जाधव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनाने का दृष्टिकोण हमारे प्रयासों में मार्गदर्शक है। उन्होंने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि ये समझौते भारत की समृद्ध औषधीय पादप विरासत संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ समेकित कर प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रगति कर रहे हैं।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ऊतक संवर्धन विधियों से दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म (पौधों और जीवों की आनुवांशिक संरचना सामग्री) का संरक्षण और रखरखाव करना है। इससे आयुष उद्योग में प्रयुक्त दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त श्रेणी के औषधीय पौधों की आपूर्ति सुगमता के लिए ऊतक संवर्धन विधियों के विकास और उनकी व्यापक खेती एवं रखरखाव द्वारा हितधारकों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और इन औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म को संरक्षित रखा जा सकेगा। समझौते में दोनों पक्ष औषधीय पादप क्षेत्र और आयुष उद्योग के विकास तथा लाभ के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों के उपयोग हेतु सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेंगे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच हुए दूसरे समझौता ज्ञापन में नई दिल्ली के एम्स परिसर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा औषधीय पौध उद्यान की स्थापना की जाएगी और औषधीय पौधों के बारे में जन जागरूकता फैलाई जाएगी।

इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और विद्यार्थियों में औषधीय पौधों के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी तथा अस्पताल परिसर में आने वाले आगंतुकों को भी लाभ मिलेगा। दोनों समझौता ज्ञापन औषधीय पौधों के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित संरक्षण तथा अनुसंधान और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के आयुष मंत्रालय के निरंतर प्रयासों की दिशा में उल्लेखनीय उपब्धि हैं।

प्राचीन स्मारकों का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया गया

नई दिल्ली – देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में 3685 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के नियमों और शर्तों के अधीन, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक अकादमी नियमित आधार पर प्रदर्शन कलाओं और अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रह के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रयास आईसीएच के डिजिटल संरक्षण में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण और आईसीएच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

आईसीएच तत्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित संगठनों, नागरिक समाज समूहों, स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, देश भर के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य और ललित कला जैसे विषयों में दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण करते हैं। इस पहल से इन परंपराओं का प्रिंट और ऑडियो-विजुअल दोनों प्रारूपों में दस्तावेज़ीकरण होता है। इसके अलावा, साहित्य अकादमी अपने "लोक: अनेक स्वर" नामक कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से जमीनी स्तर पर पारंपरिक कला रूपों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है, जिसमें व्याख्यानों के साथ-साथ प्रदर्शन भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम की परिकल्पना देश की लोक और आदिवासी कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी। एएसआई की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को यथासंभव सुगम्य बनाए, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना और भेदभाव को रोकना है, साथ ही सभी दिव्यांगजनों के समानता, सम्मान और सम्मान के अधिकार पर ज़ोर देना ताकि समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत होगा शिकायतों का निवारण

नई दिल्ली – सीपीजीआरएएमएस में 1.4.2025 से 24.7.2025 तक की अवधि में, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कुल 6,60,091 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 4,47,431 शिकायतों का निवारण 30 दिनों के भीतर किया गया, जिनका औसत निवारण समय 16 दिन रहा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। नागरिक संतुष्टि का स्वतंत्र रूप से आकलन करने के लिए, जुलाई 2022 से फीडबैक कॉल सेंटर चालू है। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

'पुणे महानगर क्षेत्र विकास केंद्र' का हुआ उद्घाटन

पुणे – कोई भी एक शहर अब किसी क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन महाराष्ट्र के कई शहर तेज़ी से विकास कर रहे हैं। हालाँकि, पुणे शहर अपार प्रगति और नवाचार का केंद्र है और नए क्षेत्रों में प्रवेश करके अपनी ताकत बनाने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि पुणे भविष्य में निश्चित रूप से तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ग्रोथ हब के माध्यम से निर्मित विकास मंच इसके लिए महत्वपूर्ण होगा।

वे नीति आयोग, महाराष्ट्र सरकार और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा यशदा में संयुक्त रूप से आयोजित 'पुणे महानगर क्षेत्र विकास केंद्र' के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधान परिषद की उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरहे, शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के प्रमुख पद्म विभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, नीति आयोग 'पुणे महानगर क्षेत्र विकास केंद्र' को गति देने के लिए काम करेगा। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए एक योजना तैयार करेगी और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसमें मदद करेगा। अगर योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए, तो जीवनशैली में आसानी भी हासिल की जा सकती है। आज, सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत शहरों के आसपास के क्षेत्रों से आता है। उचित योजना बनाकर इस विकास को गति दी जा सकती है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के गठन से एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बना है। हालाँकि, अगर इससे भी बेहतर प्रकार का औद्योगिक विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाए, तो इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि आर्थिक विकास के माध्यम से ही एक अच्छा सामाजिक वातावरण बनाया जा सकता है।

साईंनगर शिरडी और तिरुपति के बीच 18 विशेष ट्रेनें चलेगी

मुंबई – रेलवे श्रद्धालुओं के लिए साईंनगर शिरडी और तिरुपति के बीच 18 विशेष ट्रेनें चलाकर एक बड़ी सौगात दे रहा है। ये ट्रेनें दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी और श्री साईं बाबा और श्री वेंकटेश्वर के दर्शन का अनूठा अवसर प्रदान करेंगी। 07638 साप्ताहिक स्पेशल 04.08.2025 से 29.09.2025 तक प्रत्येक सोमवार को 19.35 बजे साईनगर शिरडी से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 01.30 बजे तिरुपति पहुँचेगी (9 फेरे)। 07637 साप्ताहिक स्पेशल 03.08.2025 से 28.09.2025 तक प्रत्येक रविवार को 04.00 बजे तिरुपति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.45 बजे साईनगर शिरडी पहुँचेगी (9 फेरे) ठहराव: कोपरगाँव, मनमाड, नागरसोल, औरंगाबाद, जालना, सेलू, परभणी, गंगाखेर, परली वैजनाथ, लातूर रोड, उदगीर, भालकी, बीदर, ज़ाहिराबाद, विकाराबाद, लिंगमपल्ली, सिकंदराबाद, नलगोंडा, मिर्यालगुडा, नादिकुडे, पिदुगुराल्ला, सत्तेनापल्ले, तेनाली, चिराला, ओंगोल, गुडूर और रेनिगुंटा। संरचना: दो एसी-2 टियर, 4 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सेकंड सिटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर वैन। आरक्षण: विशेष ट्रेन संख्या 07638 के लिए बुकिंग 01.08.2025 को सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू होगी। अनारक्षित डिब्बों की बुकिंग यूटीएस प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें अनारक्षित सीटों के लिए सामान्य शुल्क सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के समान होगा। इन विशेष ट्रेनों के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ या NTES ऐप डाउनलोड करें। प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग, मुख्यालय, मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा जारी की गई है।

ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव के 6 लोगों की मौत, यूक्रेन में दहशत का माहौल

कीव – रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमुर त्कачेंको ने बताया कि कम से कम 52 लोग घायल हुए हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। तिमुर त्कачेंको ने कहा कि एक नौ मंजिला रिहायशी इमारत

का बड़ा हिस्सा हमले में ढह गया है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर लिखा, "मिसाइल हमला। सीधे रिहायशी इमारत पर। लोग मलबे में दबे हुए हैं। सभी सेवाएं मौके पर हैं।"

त्कачेंको के अनुसार रूस ने इस बारकीव के कम से कम 27 स्थानों को इस हमले में निशाना बनाया गया, जिनमें सबसे अधिक नुकसान सोलोमियनस्की और स्वियातोशिन्स्की जिलों में हुआ है। घटनास्थल से आई तस्वीरों में देखा गया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारत से धुएं के गुबार उठ रहे हैं और चारों ओर मलबा बिखरा पड़ा है। रूस ने यह हमला यूक्रेन पर ऐसे वक्त में किया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति प्रयासों में प्रगति के लिए 8 अगस्त तक का समय और दे रहे हैं। अगर तब तक भी वह सीजफायर पर फैसला नहीं करते तो अमेरिका कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लागू करेगा। पश्चिमी नेताओं ने पुतिन पर यूएस-नेतृत्व वाली शांति वार्ताओं में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है ताकि वे यूक्रेन के और अधिक हिस्से पर कब्जा कर सकें।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों के लिए हुई बहस

मुंबई – 1.3.2021 तक केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पद और आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों और की गई नियुक्तियों का विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा, व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्वीकृत पदों और पदस्थ व्यक्तियों से संबंधित समेकित आंकड़ों वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट व्यय विभाग की वेबसाइट https://doe.gov.in/hi/annual-report-pay-and-allowances पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त/अपूर्ण पदों को भरने के लिए समय पर और

अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को सीधी भर्ती के पदों के संबंध में अपनी रिक्तियों की स्थिति की सूचना संबंधित भर्ती एजेंसियों को देने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी होगी ताकि सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके। पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने हेतु एक आदर्श कैलेंडर निर्धारित किया गया है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैनल समय पर तैयार हों और रिक्ति वर्ष के दौरान रिक्तियों के उत्पन्न होने पर उनका उपयोग किया जा सके। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए और उससे नीचे के पदों पर नियुक्तियाँ करने हेतु मंत्रालयों/विभागों को शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इन सभी उपायों से केंद्र सरकार में नियुक्तियों की गति और मात्रा में तेजी लाने और रिक्त पदों को भरने में उल्लेखनीय मदद मिली है।

इसके अलावा, जून 2022 से, केंद्र सरकार में रिक्त पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मिशन भर्ती के अंतर्गत मिशन-मोड में भरा जा रहा है। नियमित अंतराल पर 45-50 शहरों में रोज़गार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने में उत्प्रेरक का काम करते हैं। यह जानकारी डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

न्यूज गैलरी

आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया

नई दिल्ली – कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कौशल भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय "आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना" था। कार्यशाला में एमएसडीई, डीजीटी, एनसीवीईटी, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। कार्यशाला में विश्व बैंक और एडीबी ने भी भाग लिया, जो इस योजना का सह-वित्तपोषण कर रहे हैं। डीजीटी, एनसीवीईटी और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी द्वारा योजना की व्यापक रूपरेखा पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। कार्यशाला ने एनईपी 2020 में परिकल्पित शिक्षा और व्यवसाय के एकीकरण पर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव रजित पुन्हानी ने इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस योजना के परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जो एक नए संस्थागत ढाँचे के माध्यम से संचालित सरकारी स्वामित्व वाले, उद्योग-प्रबंधित कौशल संस्थानों के लिए एक ढाँचा तैयार करने के सरकार के समग्र इरादे को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारों को उपयुक्त आईटीआई क्लस्टरों की पहचान करने की आवश्यकता है, जिन्हें हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जा सके और संभावित एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। विशेष सचिव/महानिदेशक (प्रशिक्षण) सुश्री त्रिशालजीत सेठी ने योजना की व्यापक रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने योजना की सफलता के लिए संभावित उद्योग भागीदारों की पहचान करने की महत्ता पर भी बल दिया।

अमित शाह ने परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य के तहत अब तक 35,395 नई सहकारी समितियाँ बनाई जा चुकी हैं। भूमिहीन और पूंजीहीन व्यक्ति के लिए सहकारिता क्षेत्र से ही समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से अगले 5 वर्षों में सहकारिता समितियों द्वारा 50% दुग्ध कलेक्शन के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ा जा रहा है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार परंपरागत बीजों के लिए छोटे किसानों के साथ भी अनुबंध करेगी जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने समिति के सभी सदस्यों से अपने-अपने राज्यों में डेयरी क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए कहा जिससे सहकारिता को बल मिले। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु मंत्रालय की पहलों पर सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और श्री मुरलीधर मोहोल, समिति के सदस्य, सहकारिता मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 5 साल में देश में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत अब तक 35,395 नई सहकारी समितियाँ बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 6,182 बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (MPACS), 27,562 डेयरी और 1,651 मत्स्य सहकारी समितियाँ शामिल हैं।

8 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित, 12 मामले अदालत में दायर, 2 कृषि सेवा केंद्रों की बिक्री रोकी गई

यूरिया-डीएपी बेचने वाले कृषि सेवा केंद्रों के खिलाफ जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय द्वारा कार्रवाई

नागपुर – नागपुर जिले को खरीफ मौसम के लिए 31 अगस्त 2025 तक 42,544 मीट्रिक टन यूरिया के आवंटन की मंजूरी मिल गई है और आज 48,896 मीट्रिक टन यूरिया का 114 प्रतिशत आपूर्ति हो चुकी है। इसमें से 36,986 मीट्रिक टन यूरिया पीओएस मशीनों के माध्यम से बेचा जा चुका है और 11,910 मीट्रिक टन का शेष स्टॉक देखा जा रहा है। हालाँकि इस वास्तविक स्टॉक को पीओएस के माध्यम से बेचना अनिवार्य है, लेकिन कुछ कृषि आदान केंद्र संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन कृषि केंद्रों की पीओएस मशीनों पर स्टॉक और भौतिक निरीक्षण के दौरान मिले स्टॉक की जाँच के लिए छापेमारी शुरू की गई है। तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक और भरारी टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद, अब तक 2 कृषि सेवा केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और ओम गणेश, रोहित, हिमांशु, वैभव, मौली, श्री कृष्ण कृषि सेवा केंद्र आदि को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में लाइसेंसिंग अधिकारी और जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी के साथ सुनवाई की गई और रासायनिक उर्वरक बेचने वाले 8 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

नागपुर जिले में रासायनिक उर्वरकों के लिए कुल 1495 लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्र हैं और प्रत्येक तालुका को सौंपे गए पूर्णकालिक गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों के माध्यम से इन केंद्रों का निरीक्षण चल रहा है। इन निरीक्षकों ने अब तक रासायनिक उर्वरकों के कुल 118 नमूने लिए हैं, जिनमें से 16 नमूने अप्रमाणित पाए गए और पुलिस कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ 12 अदालती मामले दर्ज किए गए हैं। उनके पास से 1.20 मिलियन टन स्टॉक जब्त किया गया है और इसका मूल्य 1.35 लाख रुपये है। जिले में यूरिया की कमी से बचने के लिए 3550 मिलियन टन यूरिया का भंडार सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया था। तदनुसार, 3445 मिलियन टन यूरिया सुरक्षित कर लिया गया है और पूरा भंडार दो चरणों में जारी कर दिया गया है और कृषि सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। साथ ही, कृभको और एचयूएफएल कंपनियों से 3830 मिलियन टन यूरिया उर्वरक इसी सप्ताह आ रहा है, इसलिए जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी रवींद्र मनोहरे ने जिले के किसानों से यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के प्रति आश्वस्त रहने की अपील की है।

"यूरिया जिले में, पीओएस मशीन पर 11,000 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक प्रदर्शित होने के बावजूद, उर्वरक की बिक्री में अनियमितता और बिक्री में अनियमितता के कारण कुछ कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कृषि सेवा केंद्र संचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सामने के क्षेत्र में मूल्य बोर्ड और स्टॉक बोर्ड रखें, केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से उर्वरक बेचें, समय-समय पर स्टॉक बुक रखें और किसी भी उर्वरक का उपयोग न करें। यदि किसी किसान को इस संबंध में कोई शिकायत है, तो वे तुरंत कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक या जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी के निजी मोबाइल नंबर 9420971630 या नियंत्रण कक्ष में 0712-2560786 पर शिकायत दर्ज करें।" जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी ने अपील की है। खरीफ सीजन के लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति किसानों को सही गुणवत्ता और समय पर सुनिश्चित करने के लिए, नागपुर जिला कृषि विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण टीम सक्रिय हो गई है और जिला और तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों के माध्यम से कृषि आदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत, कृषि विकास अधिकारी, जिला गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सहित एक उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है और इस दल के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग, किसानों को माँग के अनुसार यूरिया और डीएपी की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता पर नज़र रख रहा है। इसी के तहत, जिला परिषद कृषि विभाग ने एक ब्लॉगस्पॉट https://adonagpur.blogspot.com/ शुरू किया है, जिसके माध्यम से जिले के सभी 1495 लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्रों में उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों की मात्रा की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई है।

वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कबूतरों को भोजन की आपूर्ति

मुंबई – कबूतरों की जान बचाना, पर्यावरण की रक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। कबूतरखाने को अचानक बंद करना उचित नहीं है, कबूतरखाने के संबंध में लिए गए निर्णयों पर अमल करते हुए वैकल्पिक उपाय किए जाने चाहिए। कबूतरखाने क्षेत्र में भोजन आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण कबूतरों को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनपा को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कबूतरों को नियंत्रित भोजन आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कबूतरों की जान बचाने और नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की पहल की है।

कबूतरखानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई। इस दौरान वे बोल रहे थे। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक कालिदास कोलंबकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कबूतरों के स्वस्थ रखरखाव और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए, उन्हें दाना डालने और न डालने के समय के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए। शहर में विभिन्न स्थानों पर कबूतरों की बड़ी संख्या के कारण श्वसन संबंधी समस्याएँ, बीट से होने वाला प्रदूषण और सार्वजनिक स्वच्छता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हालाँकि, इस संबंध में कबूतरखानों के स्वास्थ्य प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और इसके लिए संबंधित विशेषज्ञों की सहायता से एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। कबूतरों की बीट का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इस संबंध में, बीट की सफाई के लिए उपलब्ध तकनीकी समाधानों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के साथ इस बारे में चर्चा की है।

कबूतरखाने से जुड़े मुद्दों पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका को इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। न्यायालय में चल रही सुनवाई के संदर्भ में, यदि आवश्यक हुआ, तो राज्य सरकार आवश्यकतानुसार सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने मुंबई महानगरपालिका को पक्षीखाने का निर्माण और रखरखाव करने के निर्देश भी दिए।

राज्य में 'हर घर तिरंगा' अभियान - डॉ. कुलकर्णी

मुंबई – देशभर में देशभक्ति का माहौल बनाने तथा राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक तिरंगामय वातावरण बनाने के उद्देश्य से राज्य में 2 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान लागू करने के निर्देश सांस्कृतिक कार्य सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी ने दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में, सचिव डॉ. कुलकर्णी की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई। बैठक में सांस्कृतिक कार्य विभाग की उप सचिव नंदा राउत, उप सचिव महेश वल्हाल, सांस्कृतिक कार्य निदेशक विभीषण चावरे, राज्य मराठी विकास संस्था की उप निदेशक अंजलि धमाल के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ दावले, विभागीय आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। राज्य में पिछले तीन वर्षों से 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। सचिव डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि इस वर्ष अभियान तीन चरणों में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहला चरण 2 से 8 अगस्त 2025 तक, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त 2025 तक और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। पहले चरण में, 'हर घर तिरंगा' अभियान के माध्यम से तिरंगे का माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर दृश्य मीडिया का उपयोग किया जाएगा। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए, विभिन्न प्रतिस्पर्धी गतिविधियाँ लागू की जाएँगी जैसे तिरंगा स्वयंसेवकों का पंजीकरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र देना, स्कूल की दीवार पर तिरंगे के चित्र बनाना, तिरंगे से संबंधित विषयों पर प्रदर्शनी लगाना, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करना, जनता से मेरी सरकार वेबसाइट पर एक प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की अपील करना और तिरंगा राखी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। इसके साथ ही, स्कूल और कॉलेज के छात्र पत्र लिखकर उन्हें डाक सेवा के माध्यम से सैनिकों और पुलिस को भेजेंगे।

माधुरी उर्फ महादेवी हाथी को वापस लाने मुख्यमंत्री की पहल

मुंबई – नंदनी मठ (ताल शिरोल, जिला कोल्हापुर) के माधुरी हाथी को वापस नंदनी लाने की जनभावना है। इस जनभावना को ध्यान में रखते हुए, नंदनी मठ को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले में मठ के साथ पूरी तरह से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक अलग पुनर्विचार याचिका भी दायर करेगी और हाथी की वापसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। नंदनी मठ (ताल शिरोल, जिला कोल्हापुर) में माधुरी उर्फ महादेवी हाथी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में एक बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, चिकित्सा मंत्री हसन मुश्रीफ, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, नंदनी मठ के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हथिनी की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाएगी।

नंदनी मठ की परंपराओं और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माधुरी उर्फ महादेवी हथिनी को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मठ में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माधुरी हथिनी पिछले 34 वर्षों से नंदनी मठ में है। जनभावना है कि माधुरी मठ में वापस आनी चाहिए। इस जनभावना को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। मठ अपनी याचिका में राज्य सरकार को भी शामिल करे। साथ ही, वन विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अलग से विस्तृत पक्ष रखा जाएगा। इसमें उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाए गए और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हथिनी की देखभाल और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों सहित एक टीम का गठन करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो रेस्क्यू सेंटर जैसी व्यवस्था की जाएगी और उसके अनुसार सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इस याचिका में राज्य सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों की जाँच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक शासकों को शामिल किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में नागरिकों के विरुद्ध दर्ज मामले वापस लिए जाएँगे। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि वन विभाग महाराष्ट्र से बाहर ले जाए गए सभी हाथियों की जानकारी एकत्र करे। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार को नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हथिनी माधुरी को वापस लाने की पहल करनी चाहिए।

लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे के जीवन पर आधारित फिल्म रिलीज होगी

पुणे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे के जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज़ की जाएगी ताकि दुनिया को उनके संघर्ष, उनके महान कार्यों और उनके अमर साहित्य से अवगत कराया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए धन की कमी नहीं होगी और राज्य सरकार अण्णा भाऊ साठे के दिखाए मार्ग पर चलेगी। वे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे के साहित्य खंड क्रमांक 5, 6 व 7 के साहित्य विमोचन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटिल, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक अमित गोरखे, विजय शिवतारे, सुनील कांबले, हेमंत रसाने, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वेणु गोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवलंकर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ने अपनी लेखनी से क्रांति पैदा की, समाज को शक्ति और ऊर्जा दी। उन्होंने साहित्य के प्रत्येक पात्र को जीवंत किया। उनकी रचनाओं में करुणा, संवेदनशीलता, क्रांति, काव्य और सार्वभौमिकता दिखाई देती है। अण्णा भाऊ के साहित्य का दुनिया की 22 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और वे हर देश में प्रसिद्ध हैं। साथ ही, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर शोध कार्य चल रहा है। रूस में उनके प्रति सम्मान, आत्मीयता और उनके साहित्य के अध्ययन को देखकर गर्व होता है। भारत माता और मराठी माटी के इस सपूत का साहित्य सच्चे अर्थों में सार्वभौमिक बन गया है।"

अन्ना भाऊ ने कहानी, उपन्यास, लोकनाट्य, नाटक, सिनेमा, पटकथा, लावणी, पोवाड़े, यात्रा वृत्तांत सहित साहित्य की हर विधा को जीवंतता प्रदान की। वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने 49 वर्ष के जीवन में 40 से अधिक उपन्यास और विभिन्न प्रकार की रचनाएँ लिखीं। आज हज़ारों लोग उनके साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे सचमुच चलता-फिरता विश्वविद्यालय थे।

संत की मंडियाली ने समाज की असमानता पर प्रहार करते हुए समाज

को सुधारने और एकजुट करने का प्रयास किया, अन्ना भाऊ ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को उसी भावना से प्रस्तुत करते हुए, आंतरिक भावनाओं, पीड़ा और संवेदनशीलता को दर्शाते हुए कहीं भी कटुता नहीं लाई। उनका साहित्य समाज को जोड़ता है। उन्होंने पूर्णतः समतामूलक समाज बनाने का काम किया। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। रूस प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि वे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आए हैं और वीरों को श्रद्धांजलि देने यहां आए हैं। उन्होंने प्रेरक विचार देते हुए कहा कि अवसाद तलवार पर जमी धूल के समान है, धूल झाड़ने पर तलवार फिर से धारदार हो जाती है, धरती शेषनाग के सिर पर नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता की हथेली पर टिकी होती है। अन्नाभाऊ का व्यक्तित्व उनके संघर्षपूर्ण जीवन से निखर कर आया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा, प्रेरणा, आम आदमी को शक्ति और वंचितों को स्वर देने का काम किया। इस कार्य को समाज तक पहुँचाने का कार्य जारी है। समाज के मूल सिद्धांतों को बताने वाला और संवेदनाओं को जीवित रखने वाला ऐसा अमर साहित्य हर अगली पीढ़ी तक पहुँचे, इस दृष्टि से शोध कार्य होना चाहिए। साहित्य रत्न और लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के स्मारक के लिए 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं और स्मारक की योजना भी तैयार कर ली गई है। आने वाले समय में स्मारक का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

लोकतांत्रिक अन्ना भाऊ साठे की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, अन्ना भाऊ एक साहित्यिक, साहसी, जुझारू व्यक्तित्व थे, वे पहले दलित विद्रोही लेखक थे जिन्होंने स्थापित मराठी साहित्य, संस्कृति और परंपराओं को खारिज किया। उनका साहित्य ज्ञानवर्धक और परिवर्तनकारी था। उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में वंचितों, दलितों, मजदूर वर्ग, महिलाओं और घुमक्कड़ों के दर्द और पीड़ा को प्रस्तुत करने का काम किया। उनकी कहानियों और कविताओं ने श्रमिकों के श्रम की प्रशंसा की और जमींदारों के शोषण की निंदा की। अन्ना भाऊ की जयंती के अवसर पर, कहानियों, लोक नाटक, नाटक, कविता और यात्रा वृत्तांतों का एक खंड पाठक के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जो मराठी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।